[2016) 8 एस. सी. आर. 477

सरकार के प्रमुख सचिव, (चेन्नई) तमिलनाडु और अन्य

बनाम

पशु कल्याण बोर्ड और अन्य

(पुनरीक्षण याचिका (सिविल) सं. 3769/2016)

(सिविल अपील सं. 5387/2014)

16 नवंबर, 2016

[दीपक मिश्रा और आर. एफ. नरीमन, जे. जे.]

भारत का संविधान-अनुच्छेद 254 (1) और 25 और 7 अनुसूची, सूची 2 प्रविष्टि 14 और 15; सूची III. प्रविष्टि 17-जल्लीकट्टू अधिनियम, 2009 और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के बीच विरोध-ए. नागराजा के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि 1960 के अधिनियम की उप धारा 3 और 11 के तहत गारंटीकृत 'बैलों' के अधिकारों को छीन नहीं लिया जा सकता है और 2009 का अधिनियम 1960 के अधिनियम के प्रतिकूल है और इसलिए अनुच्छेद 254 (1) का उल्लंघन करने के कारण अमान्य है-इस आधार पर पुनरीक्षण याचिका कि 2009 का अधिनियम सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टियों 14 और 15 के दायरे में आएगा, वही 1960 के अधिनियम के प्रतिकूल नहीं हो सकता है और जल्लीकट्टू को धर्म से जुड़ी एक सामाजिक-सांस्कृतिक घटना होने के कारण, अनुच्छेद 25 का संरक्षण प्राप्त हैः जब एक घटना (जल्लीकट्टू) के उद्देश्य से एक 'बैल' को वश में किया जाता है, तो मूल अवधारणा पशु के कल्याण के लिए केंद्र में चलती है जो 1960 के अधिनियम की मूल

नींव है-1960 के अधिनियम और 2009 के अधिनियम-2009 के बीच सामने की टक्कर और विसंगति है अधिनियम सूची II की प्रविष्टियों 14 और 15 द्वारा कवर नहीं किया गया है-'जल्लीकट्टू' की गतिविधि पूरी तरह से सूची III की प्रविष्टि 17 के भीतर आती है और इसलिए इसका परीक्षण तिरस्कार के आधार पर किया जाना चाहिए-जल्लीकट्टू को भी अनुच्छेद 25 के तहत गारंटीकृत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से जोड़ा नहीं जा सकता है-तमिलनाडु जल्लीकट्टू अधिनियम, 2009 का विनियमन-धारा 2 (सी) और 3-पशु क्रूरता रोकथाम अधिनियम कानूनी प्राधिकरण-प्रेरक प्राधिकरण-कानून और कानूनी सिद्धांतों से निपटने के दौरान, सांस्कृतिक लोकाचार, प्राचीन ग्रंथों और अंतर्राष्ट्रीय धारणाओं का संदर्भ अनुचित नहीं है, जहां तक वे संवैधानिक और वैधानिक विचार और सिद्धांत के विपरीत नहीं हैं। पुनरीक्षण याचिकाओं को खारिज करते हुए, अदालत ने कहाः 1. तमिलनाडु जल्लीकट्टू अधिनियम, 2009 की सावधानीपूर्वक जांच करने पर, यह स्पष्ट है कि घटनाओं में बैलों को वश में करना शामिल हो सकता है और जल्लीकट्टू को एक कार्यक्रम के रूप में नामित किया गया है। यह नहीं कहा जा सकता है कि 'जल्लीकट्टू' की घटना में बैलों को शामिल करते समय उनके साथ कोई क्रूरता नहीं की जाती है। [पैरा 17) [489-एफ-जी; 490-ई)

1.2 जब दोनों अधिनियम अर्थात पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 और 2009 अधिनियम, ये हैंः संयोजन में विश्लेषण किया गया है, यह पाया गया है कि जब किसी घटना के उद्देश्य से एक बैल को "वश में" किया जाता है, तो मौलिक अवधारणा पशु के कल्याण के विपरीत होती है, जो 1960 के अधिनियम की मूल नींव है। 1960 के अधिनियम और 2009 के अधिनियम के बीच एक प्रत्यक्ष टकराव और स्पष्ट विसंगति है। यह अकल्पनीय है कि एक बैल जो एक घरेलू जानवर है, उसे मनोरंजन के लिए वश में किया जाना चाहिए और एक विस्तृत आधार प्रस्तुत किया जा सकता है कि यह एक टिकट वाला शो नहीं है, बल्कि फसल के त्योहार को मनाने के लिए है।

कुछ लोगों को आनंद देने के लिए इस तरह का उत्सव, दोनों भाग लेने वाले और इसे देखने वाले लोग, एक ऐसा कार्य है जो जानवरों के कल्याण के खिलाफ है और निश्चित रूप से जानवरों के साथ क्रूरता के साथ व्यवहार करने के बराबर है। [पैरा 25) (494-बी-सी)

दीप चंद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य ए. आई. आर. 1959 एस. सी. 648:1959 पूरक एस. सी. आर. 8: एम. करुणानिधि बनाम भारत संघ (1979) 3 एस. सी. सी. 431:1979 (3) एस. सी. आर. 254-इसके बाद आया। ज़वेरीभाई अमैदास बनाम बॉम्बे राज्य (1955) 1 एससीआर 799; उड़ीसा राज्य बनाम एम.ए. टुलोच एंड कंपनी (1964) 4 एस. सी. आर. 461-पर निर्भर था।

1.3 संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 2 की न तो प्रविष्टि 14 और न ही प्रविष्टि 15 में 2009 के अधिनियम को शामिल किया जाएगा। प्रविष्टि 14, यहाँ तक कि दूर से भी, जल्लीकट्टू से कोई लेना-देना नहीं है, जो एक कार्यक्रम है। केवल इसलिए कि यह आयोजन कृषि के बाद होता है, इसे कृषि से जोड़ा नहीं जा सकता है। प्रविष्टि 15 का उद्देश्य राज्य विधानमंडल को पशुओं के संरक्षण, संरक्षण और सुधार और किसी भी प्रकार के पशु रोगों को रोकने के संबंध में कानून बनाने की शक्ति प्रदान करना है। जल्लीकट्टू गतिविधि पूरी तरह से सूची III की प्रविष्टि 17 के भीतर आती है और इसलिए, इसका प्रतिकूलता के आधार पर परीक्षण किया जाना चाहिए। 1960 का अधिनियम और 2009 का अधिनियम समवर्ती सूची की प्रविष्टि 17 के आधार पर है। इन दोनों अधिनियमों के बीच विरोधाभास है और इसलिए राज्य अधिनियम को अधिकार से बाहर घोषित किया गया है। प्रविष्टि 17 पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम से संबंधित है और 1960 का अधिनियम पूरे क्षेत्र को शामिल करता है। इसके विपरीत, 2009 का अधिनियम बैलों को वश में करने की अनुमति देता है। इस प्रकार, दोनों

सह-अस्तित्व में नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वे असंगत हैं। [पैरा 28,31] [494-ई, जी-एच; 495-एफ-एच]

आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य बनाम मैकडॉवेल एंड कंपनी और अन्य। (1996) 3 धारा 709:1996 (3) एस. सी. आर. 721; आई. टी. सी. लिमिटेड बनाम कृषि उपज बाजार समिति और अन्य (2002) 9 एस. सी. सी. 232:2002 (1) एस. सी. आर. 441-निर्दिष्ट।

1.4 संविधान का अनुच्छेद 25 "धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार" शीर्षक के तहत आता है, यह अधिकार विवेक की स्वतंत्रता और किसी भी धर्म का पालन करने और उसे मानने के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के साथ जल्लीकट्टू का कोई संबंध या संबंध नहीं है। यह कहना सही नहीं है कि जब जल्लीकट्टू एक ऐसा कार्यक्रम है जो फसल कटाई के बाद होता है, तो इसका धार्मिक स्वाद होता है। इस तरह की अवधारणा अनुच्छेद 25 के मौलिक पहलू से पूरी तरह से अलग है। [पैरा 32,33 और 36] (496-डी, जी-एच; 498-सी-डी) रतिलाल पनाचंद गांधी और अन्य बनाम स्टेट ऑफ बॉम्बे एंड अन्य ए. आई. आर. 1954 एस. सी. 388:1954 एस. सी. आर. 1035-इसके बाद आया। आयुक्त, हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती, मद्रास बनाम श्री शिरूर मठ ए. आई. आर. 1954 एस. सी. 282:1954 एस. सी. आर. 1005 के श्री लक्ष्मींद्र तीर्थ स्वामी; सरदार सैयदना ताहिर सैफुद्दीन साहेद बनाम बॉम्बे राज्य ए. आई. आर. 1962 एस. सी. 853:1962 पूरक एस. सी. आर. 496-पर भरोसा किया। 2. न्यायालय, कानून और कानूनी सिद्धांतों पर विचार करते समय इस देश के सांस्कृतिक लोकाचार और प्राचीन ग्रंथों का उल्लेख कर सकता है जहां तक कि वे संवैधानिक और वैधानिक विचार और सिद्धांत के विपरीत नहीं हैं। जहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय अवधारणा का संबंध है जो इस सोच से संबंधित है कि "जिस दुनिया को बड़ा माना

जाता है वह उतनी बड़ी नहीं है" या उस मामले के लिए विभिन्न अवधारणाओं का पालन करना जो जानवरों के साथ सहयोग और उठाए गए कदमों से संबंधित हैं। इसमें कोई कानूनी दुर्बलता नहीं है। यह नहीं कहा जा सकता है कि संदर्भ अनुचित है। इसके विपरीत, वे एक समग्र विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं जो भारत के संवैधानिक मूल्य के अनुरूप है। करूणा के दर्शन में कई प्रकार की अभिव्यक्तियाँ हो सकतीहैं।[पैरा21)(492-बी-डी)

भारतीय पशु कल्याण बोर्ड बनाम ए. नागराजा और अन्य। (2014) 7 एससीसी 547:2014 (60) एससीआर 646-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भः- 2014 (60) एस. सी. आर. 646 पैरा 3 1959 अनुपूरक एस. सी. आर. 8 पैरा 21, (1979) (3) एस. सी. आर. 254 पैरा 23 (1955) 1 एस. सी. आर. 799 पैरा 23 (1964) 4 एस. सी. आर. 461 पैरा 24 1996 (3) एस. सी. आर. 721 पैरा 29 2002 (1) एस. सी. आर. 441 पैरा 30 1954 एस. सी. आर. 1035, पैरा 33 1954 एस. सी. आर.1005 पैरा 34 1962 अनुपूरक एस. सी. आर. 496 पैरा 35 पर निर्भर था।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः- 2014 की सिविल अपील सं. 5387 में 2016 में पुनरीक्षण याचिका (सिविल) सं.3769

2006 के डब्ल्यू. पी. सं. 11478 के साथ 2014 की सिविल अपील संख्या 5387 में 2016 की पुनरीक्षण याचिका (सिविल) संख्या 3770 में मदुरै पीठ में मद्रास उच्च न्यायालय के 09.03.2007 के निर्णय और आदेश से।

पी. एस. नरसिम्हा, ए. एस. जी., सिद्धार्थ लूथरा, आनंद ग्रोवर, एम. एस. गणेश, डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी, शेखर नाफड़े, श्री सुब्रमण्यम प्रसाद, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री अपामा भट, मयंक सप्रा, शफीक खान, सुश्री अंजलि शर्मा, बलराज दीवान, सुश्री सुप्रिया

जुनेजा, पुरुषोत्तम शर्मा त्रिपाठी, मुकेश कुमार सिंह सुश्री श्रीनिवासन प्रिया, रवि चंद्र प्रकाश, अजीत शर्मा, सुबोध एस. पाटिल, एम. योगेश कन्ना, दीपक आनंद, गुरमीत सिंह मक्कर, अनिल कुमार मिश्रा-I, अंकुर एस. कुलकर्णी, बिजन कुमार घोष, सी. के. सासी, मनुकृष्णन, निशांत रमाकांतराव कटनेश्वरकर, रवींद्र केशवराव अदसुरे, विष्णु शर्मा, सुश्री लेमैक्स लॉयर्स एंड कंपनी, सुश्री नरेश बख्शी उपस्थित पक्षों की ओर से अधिवक्ता।

1. आम तौर पर, पुनर्विचार याचिकाओं को प्रसारित किया जाता है और उसमें उठाए गए आधारों की विवेचना करने पर, उन्हें या तो खारिज कर दिया जाता है या खुले न्यायालय में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाता है। तमिलनाडु राज्य की ओर से प्रस्तुत तर्कों की प्रतिरक्षात्मकता का परीक्षण करने के लिए खुली अदालत में सुनवाई के लिए वर्तमान पुनरीक्षण याचिका को सूचीबद्ध किया गया है। यह ध्यान दिया जाए कि वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने सुनवाई की शुरुआत में कहा कि उन्हें पशु कल्याण बोर्ड की ओर से पेश होने और पुनरीक्षण के लिए आवेदन में मांगी गई प्रार्थनाओं का विरोध करने के निर्देश इस आधार पर हैं कि यह न्यायालय पुनरीक्षण के लिए आवेदन पर विचार करते समय अपीलीय अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं करता है। उक्त भवन की संरचना करते हुए वह प्रस्तुत करेंगे कि पुनरीक्षण के लिए आवेदन में स्थान पाने वाले प्रत्येक आधार को अपील में उठाया जाना उचित आधार हो सकता है, लेकिन पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के उद्देश्य से इस पर विचार करना बिल्कुल अनुचित है।

2. पुनरीक्षण याचिका के निर्णय के लिए कुछ तथ्यों को बताना आवश्यक है। 11 जुलाई, 2011 को पर्यावरण और वन मंत्रालय ने पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 (संक्षिप्तता के लिए, पी. सी. ए. अधिनियम) की धारा 22 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए एक अधिसूचना जारी की, जो पूर्ववर्ती सामाजिक न्याय और अधिकारिता

मंत्रालय जी.एस.आर. संख्या 619 (ई) दिनांक 14-10-1998 में भारत सरकार की अधिसूचना का स्थान लेती है। अधिसूचना के प्रासंगिक भाग को नीचे निकाला गया हैः-"ऐसे सुपर सत्र से पहले किए गए या किए जाने वाले कार्यों को छोड़कर, केंद्र सरकार एतद्द्वारा निर्दिष्ट करती है कि निम्नलिखित जानवरों को प्रदर्शन करने वाले जानवरों के रूप में प्रदर्शित या प्रशिक्षित नहीं किया जाएगा, जो इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा, अर्थात्ः -1. भालू 2. बंदर 3. बाघ 4. पैंथर्स 5. शेर 6. बैल।

3. उक्त अधिसूचना को मौन रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी। उक्त अधिसूचना को बॉम्बे उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी जिसने अधिसूचना की वैधता को बरकरार रखा था। इस बीच, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि तमिलनाडु जल्लीकट्टू विनियमन अधिनियम, 2009 (संक्षिप्तता के लिए, '2009 अधिनियम') की संवैधानिक वैधता पर मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष सवाल उठाया गया था, जिसने इसे बरकरार रखा। बॉम्बे और मद्रास के उच्च न्यायालयों के फैसलों पर विभिन्न पक्षों द्वारा इस न्यायालय के समक्ष हमला किया गया था और इस न्यायालय ने भारतीय पशु कल्याण बोर्ड बनाम ए. नागराजा और अन्य के विवाद पर ध्यान केंद्रित किया। यहां यह उल्लेख करना उपयुक्त है कि पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स (पेटा) द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक रिट याचिका भी दायर की गई थी। इन सभी मामलों को एक सामान्य निर्णय द्वारा निपटाया गया था जिसमें इस न्यायालय ने कई पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अपना निष्कर्ष दर्ज किया और कुछ निर्देश जारी किए जो नीचे पुनः प्रस्तुत किए गए हैंः-

"हम घोषणा करते हैं कि पी. सी. ए. अधिनियम की धारा 5 आई. ए. (जी) और (एच) के साथ पठित पी. सी. ए. अधिनियम की धारा 3 और 11 के तहत बैलों को गारंटीकृत

अधिकारों को पी. सी. ए. अधिनियम की धारा 11 (3) और 28 के अलावा अलग नहीं किया जा सकता है या कम नहीं किया जा सकता है 2) हम घोषणा करते हैं कि जिन पांच स्वतंत्रताओं को पहले पीसीए अधिनियम की धारा 3 और 11 में पढ़ा गया था, उन्हें राज्यों, केंद्र सरकार, केंद्र शासित प्रदेशों ("सरकारों" में), एम. ओ. ई. एफ. और ए. डब्ल्यू. बी. आई. द्वारा संरक्षित और संरक्षित किया जाएगा। 3) ए. डब्ल्यू. बी. आई. और सरकारों को यह देखने के लिए उचित कदम उठाने का निर्देश दिया जाता है कि पशुओं के प्रभारी या उनकी देखभाल करने वाले व्यक्ति पशुओं की भलाई सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय करें। 4) ए. डब्ल्यू. बी. आई. और सरकारों को निर्देश दिया जाता है कि वे जानवरों को अनावश्यक दर्द या पीड़ा से बचाने के लिए कदम उठाएं, क्योंकि उनके अधिकारों को पी. सी. ए. अधिनियम की धारा 3 और 11 के तहत वैधानिक रूप से संरक्षित किया गया है। 5) ए. डब्ल्यू. बी. आई. को यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि धारा 11 (l) (एम) (ii) के प्रावधानों का ईमानदारी से पालन किया जाए, जिसका अर्थ है कि पशु का प्रभारी या देखभाल करने वाला व्यक्ति किसी भी पशु को किसी मनुष्य या किसी अन्य पशु के खिलाफ लड़ने के लिए नहीं उकेरेगा। 6) ए. डब्ल्यू. बी. आई. और सरकारें यह भी देखेंगे कि जिन मामलों में धारा 11 (3) शामिल है, वहां भी जानवरों को अनावश्यक पीड़ा और पीड़ा नहीं दी जाए और इसे प्राप्त करने के लिए पर्याप्त और वैज्ञानिक तरीके अपनाए जाएं। 7) एडब्ल्यूबीआई और सरकारों को संविधान के अनुच्छेद 51 ए (जी) और (एच) की भावना को विकसित करते हुए धारा 9 (के) के अनुसार जानवरों के साथ मानव व्यवहार के संबंध में शिक्षा प्रदान करने के लिए कदम उठाने चाहिए। 8) संसद से अपेक्षा की जाती है कि वह अधिनियम के उद्देश्य और उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक प्रभावी निवारक प्रदान करने के लिए पी. सी. ए. अधिनियम में उचित संशोधन करे और धारा 11 के उल्लंघन के लिए पर्याप्त दंड और दंड लगाया जाना चाहिए। 9) यह उम्मीद की जाती है कि संसद जानवरों के

अधिकारों को संवैधानिक अधिकारों तक बढ़ाएगी, जैसा कि दुनिया भर के कई देशों द्वारा किया गया है, ताकि उनकी गरिमा और सम्मान की रक्षा की जा सके। 10) सरकार यह देखेगी कि यदि पी. सी. ए. अधिनियम के प्रावधानों और इस न्यायालय द्वारा जारी घोषणाओं और निर्देशों का ठीक से और प्रभावी ढंग से पालन नहीं किया जाता है, तो गलती करने वाले अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए ताकि पी. सी. ए. अधिनियम के उद्देश्य और उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। 11) टी. एन. आर. जे. अधिनियम पी. सी. ए. अधिनियम के प्रतिकूल पाया जाता है, जो एक कल्याणकारी कानून है, इसलिए इसे संवैधानिक रूप से अमान्य माना जाता है, जो उल्लंघनकारी या भारत के संविधान के अनुच्छेद 254 (I) का उल्लंघन करता है। 12) ए. डब्ल्यू. बी. आई. को एस. पी. सी. ए. के परामर्श से पी. सी. ए. अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए प्रभावी और त्वरित कदम उठाने और सरकारों को समय-समय पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाता है और यदि कोई उल्लंघन देखा जाता है, तो सरकारों को उचित अनुवर्ती कार्रवाई सहित इसके समाधान के लिए कदम उठाने चाहिए। आवेदन के समर्थन में, तमिलनाडु राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री शेखर नाफडे ने तर्क दिया है कि न्यायालय 2009 के अधिनियम को पी. सी. ए. अधिनियम के प्रावधानों के प्रतिकूल मानते हुए और राज्य अधिनियम को असंवैधानिक घोषित करने में विफल रहा है। विद्वान वरिष्ठ वकील के अनुसार, कोई प्रतिकूलता नहीं है क्योंकि 2009 का अधिनियम बैलों की रक्षा करता है और जानवर के साथ किसी भी क्रूर व्यवहार का सुझाव नहीं देता है।

4. यह उनका निवेदन है कि संविधान के अनुच्छेद 254 (1) के संदर्भ में समझ में आने वाली तिरस्कार की अवधारणा को तथ्यात्मक मैट्रिक्स पर गलत तरीके से लागू किया गया है और इसलिए, निर्णय की पुनरीक्षण की आवश्यकता है। विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे कहा कि जल्लीकट्टू एक सामाजिक-सांस्कृतिक कार्यक्रम है जिसका धर्म

से संबंध है और इसलिए इसे संविधान के अनुच्छेद 25 का संरक्षण प्राप्त है और ऐसे तथ्यात्मक परिदृश्य में 2009 के अधिनियम को अधिकार से बाहर घोषित करना गलत है जिसकी पुनरीक्षण की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया है कि न्यायालय ने तिरस्कार पर अपनी राय में पूरी तरह से त्रुटि की है, क्योंकि 2009 का अधिनियम सूची II की प्रविष्टियों 14 और 15, यानी राज्य सूची के दायरे में आएगा और इसलिए, केवल राज्य विधायिका को उक्त क्षेत्र में कानून बनाने की क्षमता है और तिरस्कार का सवाल ही पैदा नहीं होता है। उन्होंने हमें अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के बारे में व्यापक रूप से बताया है, जिन पर हम अपने विचार-विमर्श के दौरान विज्ञापन देंगे।

5. डॉ. सिंघवी, विद्वान वरिष्ठ वकील, जिन्होंने कैविएट में प्रवेश किया है, प्रस्तुत करेंगे कि ए. नागराजा (उपरोक्त) में दो-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा तिरस्कार के संबंध में किए गए विश्लेषण को दीप चंद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य मामलों में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों को देखते हुए त्रुटिपूर्ण नहीं माना जा सकता है। उनके द्वारा यह आग्रह किया जाता है कि दोनों अधिनियमों के बीच सीधा टकराव हो क्योंकि एक पशुओं के कल्याण के लिए है जो उनके साथ दया और करुणा के साथ व्यवहार करते हैं और दूसरा उन्हें हीन सुखों को संतुष्ट करने के लिए एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मजबूर करता है जो मनुष्य के रोमांच (काल्पनिक रूप से एक खेल कहा जाता है) से जुड़े होते हैं। इसके अतिरिक्त, डॉ. सिंघवी द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि 1960 का अधिनियम पूरे क्षेत्र को शामिल करता है और राज्य विधानमंडल के लिए ऐसा कानून लाने की कोई गुंजाइश नहीं है जो पीसीए अधिनियम के विपरीत हो। उनके द्वारा आगे यह आग्रह किया जाता है कि राज्य के विधान का राज्य सूची की प्रविष्टियों 14 और 15 के साथ कोई संबंध नहीं है, लेकिन दोनों अधिनियमों की जड़ें समवर्ती सूची की प्रविष्टि 17 में हैं।

6. डॉ. सिंघवी के निवेदन के जवाब में, श्री नाफडे ने तर्क दिया है कि केंद्रीय अधिनियम ने पूरी तरह से क्षेत्र को शामिल नहीं किया है और किसी भी मामले में, किसी भी तरह से अतिव्यापी हो सकता है और इसलिए, इस न्यायालय को अधिनियम को बनाए रखने और निर्णय की पुनरीक्षण करने के लिए पीठ और सार के सिद्धांत को लागू करना चाहिए, भले ही इसे समवर्ती सूची का विषय माना जाए।

7. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों की सराहना करने के लिए, दोनों अधिनियमों के उद्देश्य और योजना को समझना आवश्यक है। 1960 के अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों का विवरण इस प्रकार हैः-"उद्देश्यों और कारणों का विवरण भारत सरकार द्वारा नियुक्त पशु क्रूरता रोकथाम समिति ने पशु क्रूरता रोकथाम अधिनियम, 1890 (1980 का केंद्रीय अधिनियम) में कई कमियों की ओर ध्यान आकर्षित किया और एक अधिक व्यापक अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित करने का सुझाव दिया। मौजूदा अधिनियम का दायरा इस प्रकार सीमित हैः (।) यह केवल नगरपालिका सीमाओं के भीतर शहरी क्षेत्रों पर लागू होता है; (2) यह 'पशु' शब्द को किसी भी घरेलू या पकड़े गए जानवर के रूप में परिभाषित करता है और इस प्रकार इसमें घरेलू और पकड़े गए जानवरों के अलावा अन्य जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम का कोई प्रावधान नहीं है; (3) इसमें केवल कुछ निर्दिष्ट प्रकार की जानवरों के प्रति क्रूरता शामिल है; और (4) कुछ अपराधों के लिए दंड अपर्याप्त हैं। इस विधेयक का विस्तार समिति की उन सिफारिशों को प्रभावी बनाने के लिए किया गया है जिन्हें भारत सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और जिनके संबंध में केंद्रीय विधान बनाया जा सकता है। मौजूदा अधिनियम को बदलने का प्रस्ताव है। पशुओं के प्रति कुछ प्रकार की क्रूरता को अपराध घोषित करने और ऐसे अपराधों के लिए आवश्यक दंड प्रदान करने और उनमें से कुछ को अधिक गंभीर बनाने के अलावा, विधेयक में पशु कल्याण के उपायों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना के प्रावधान भी हैं। पशुओं पर प्रयोग को नियंत्रित करने के

लिए एक समिति की स्थापना के लिए भी प्रावधान किए जा रहे हैं, जब सरकार, पशु कल्याण बोर्ड की सलाह पर, संतुष्ट हो जाती है कि प्रयोग के दौरान पशुओं के प्रति क्रूरता को रोकने के लिए ऐसा करना आवश्यक है। विधेयक में टिकटों की बिक्री के माध्यम से जनता को प्रवेश दिए जाने वाले किसी भी मनोरंजन के उद्देश्य से जानवरों के प्रशिक्षण और प्रदर्शन को लाइसेंस देने और विनियमित करने के प्रावधान भी हैं।

8. पी. सी. ए. अधिनियम की प्रस्तावना में यह अभिधारणा दी गई है कि अधिनियम का उद्देश्य जानवरों को अनावश्यक दर्द या पीड़ा से बचाना है और इसलिए, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम से संबंधित कानून में संशोधन करने की आवश्यकता महसूस की गई। पी. सी. ए. अधिनियम की धारा 2, जो शब्दकोश खंड है, धारा 2 (ए) के तहत 'पशु' शब्द को परिभाषित करती है। "पशु" का अर्थ है मनुष्य के अलावा कोई अन्य जीवित प्राणी। धारा 2 (डी) जो घरेलू जानवर को इस प्रकार परिभाषित करती हैः-"घरेलू जानवर" का अर्थ है कोई भी जानवर जिसे वश में किया गया है या जिसे मनुष्य के उपयोग के लिए किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त रूप से वश में किया गया है या किया जा रहा है या जो, हालांकि इसे न तो वश में किया गया है और न ही किया जा रहा है और न ही ऐसा करने का इरादा है, वास्तव में पूरी तरह से या आंशिक रूप से वश में किया गया है।

9. धारा 3 पशुओं के प्रभारी व्यक्तियों के कर्तव्यों को सूचीबद्ध करती है। उक्त प्रावधान इस प्रकार हैः-"पशुओं के प्रभारी व्यक्तियों के कर्तव्य-किसी भी पशु की देखभाल या प्रभारी रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य होगा कि वह ऐसे पशु की भलाई सुनिश्चित करने के लिए सभी उचित उपाय करे और ऐसे पशु को अनावश्यक दर्द या पीड़ा से पीड़ित होने से रोके।"

10. पी. सी. ए. अधिनियम की धारा 11 जो पशुओं के प्रति क्रूरता से संबंधित अध्याय रोग में आती है, आम तौर पर ऐसी कई स्थितियों का प्रावधान करती है जहां पशुओं को क्रूरता का सामना करना पड़ता है। धारा 11 (I) (a) निम्नानुसार हैः-"11 (2) (a). पिटाई, लात, ओवर-राइड, ओवर-ड्राइव, ओवर-लोड, यातना या अन्यथा किसी भी जानवर के साथ ऐसा व्यवहार करता है ताकि उसे अनावश्यक दर्द या पीड़ा हो या मालिक की अनुमति से किसी भी जानवर के साथ ऐसा व्यवहार किया जा सके।

11. उक्त परिभाषा के एक सादे अध्ययन पर, यह काफी स्पष्ट है कि एक व्यक्ति किसी जानवर के साथ अन्यथा व्यवहार नहीं कर सकता है ताकि उसे अनावश्यक दर्द या पीड़ा हो। धारा 11 (2) (एम), जिसे जुलाई, 1982 से प्रभाव के साथ लागू किया गया है, इस प्रकार हैः-"11 (2) (एम). केवल मनोरंजन प्रदान करने की दृष्टि से (i) किसी भी जानवर को सीमित करता है या उसे सीमित करता है (जिसमें किसी जानवर को बाघ या अन्य अभयारण्य में चारा के रूप में बांधना शामिल है) ताकि उसे किसी अन्य जानवर के लिए शिकार की वस्तु बनाया जा सके; या (ii) किसी भी जानवर को किसी अन्य जानवर से लड़ने या चारा बनाने के लिए उकसाया जा सके।

12. उपरोक्त प्रावधान किसी जानवर को किसी अन्य जानवर से लड़ने या लालच देने के लिए उकसाने पर जोर देता है। धारा 11 की उप-धारा (3) में कुछ अपवाद दिए गए हैं जो इस प्रकार हैंः-"इस धारा में कुछ भी लागू नहीं होगा-(ए) निर्धारित तरीके से मवेशियों की नसबंदी, या किसी भी जानवर की नपुंसकता या ब्रांडिंग या नाक-रोपिंग; या (बी) घातक कक्षों में या ऐसे अन्य तरीकों से आवारा कुत्तों का विनाश जो निर्धारित किए जा सकते हैं; या (सी) किसी भी कानून के अधिकार के तहत किसी भी जानवर का उन्मूलन या विनाश; या (डी) अध्याय IV में निपटा गया कोई मामला; या (ई) मानव जाति के लिए भोजन के रूप में किसी भी जानवर को नष्ट करने या नष्ट करने

की तैयारी के दौरान किसी भी कार्य को करना या छोड़ना जब तक कि ऐसा विनाश या तैयारी के साथ न हो।

13. उक्त उप-धारा के अवलोकन पर, यह काफी अस्पष्ट है कि यह मानव आवश्यकता, जीवन के अस्तित्व और कुछ अन्य पहलुओं के सिद्धांत पर अंतर्निहित है और यही कारण है कि निर्णय इसे "आवश्यकता के सिद्धांत" के शीर्षक के तहत रखता है।

14. धारा 21 और 22 प्रदर्शन करने वाले जानवरों से संबंधित हैं। उक्त प्रावधान नीचे पुनः प्रस्तुत किए गए हैंः-

> "21. "प्रदर्शनी" और "प्रशिक्षण" को परिभाषित किया गया है- इस अध्याय में, "प्रदर्शनी" का अर्थ है किसी भी मनोरंजन में प्रदर्शन, जिसमें जनता को टिकटों की बिक्री के माध्यम से प्रवेश दिया जाता है और "ट्रेन" का अर्थ है ऐसी किसी प्रदर्शनी के उद्देश्य के लिए प्रशिक्षण, और "प्रदर्शक" और "प्रशिक्षक" अभिव्यक्तियों के क्रमशः संबंधित अर्थ हैं।
>
> 22. प्रदर्शन करने वाले जानवरों की प्रदर्शनी और प्रशिक्षण पर प्रतिबंध- कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रदर्शन करने वाले जानवर को तब तक प्रदर्शित या प्रशिक्षित नहीं करेगा जब तक कि वह इस अध्याय के प्रावधानों के अनुसार पंजीकृत न हो।
>
> (ii) एक प्रदर्शन करने वाले जानवर के रूप में, कोई भी जानवर जिसे केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा,

एक जानवर के रूप में निर्दिष्ट कर सकती है जिसे प्रदर्शन करने वाले जानवर के रूप में प्रदर्शित या प्रशिक्षित नहीं किया जाएगा।

15. पी. सी. ए. अधिनियम की शरीर रचना को स्कैन करने के बाद, 2009 के अधिनियम को श्री नाफडे के रूप में संदर्भित करना हमारी ओर से अनिवार्य है, विद्वान वरिष्ठ वकील इस बात पर जोर देंगे कि अधिनियम का उद्देश्य तमिलनाडु राज्य में जल्लीकट्टू को विनियमित करना है और इसलिए, यह बैलों के साथ किसी भी प्रकार की क्रूरता का व्यवहार करने का इरादा नहीं रखता है। "जल्लीकट्टू" को धारा 2 (सी) के तहत परिभाषित किया गया है, जो इस प्रकार हैः-"2 (सी). "जल्लीकट्टू" में "मंजुविरट्टू", "ऊर्मादु", "वडामादु", "एरुधु विडुम विझा" और ऐसे सभी कार्यक्रम शामिल हैं जिनमें बैलों को वश में करना शामिल है।

16. 2009 के अधिनियम की धारा 3 जल्लीकट्टू के आयोजन को एक "कार्यक्रम" के रूप में मानती है। धारा 4 आयोजक की जिम्मेदारी बताती है जो कार्यक्रम का आयोजन करता है। धारा 5 जिले के कलेक्टर से व्यवस्था करने की अपेक्षा करती है। हम मानते हैं कि धारा 5 को पूरी तरह से पुनः प्रस्तुत करना उचित है। यह नीचे लिखा हैः-"5. कलेक्टर-(i) कम से कम छह फीट की ऊंचाई पर अखाड़े में दो बार बैरिकेडिंग सुनिश्चित करेंगे ताकि बैल दो बार बैरिकेडिंग से न कूदें और दर्शकों को चोट न पहुंचे; (ii) यह सुनिश्चित करें कि गैलरी में दर्शकों की संख्या लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक न हो; (iii) यह सुनिश्चित करें कि डबल बैरिकेडिंग और गैलरी की सुरक्षा के लिए लोक निर्माण विभाग से सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है; (iv) यह सुनिश्चित करें कि बैल किसी भी बीमारी से मुक्त हैं और उन्हें अधिक आक्रामक या उग्र बनाने के उद्देश्य से निकोटीन, कोकीन जैसे किसी भी पदार्थ से नशा या प्रशासित नहीं किया गया है; (v) उन स्थानों पर पर्याप्त पुलिस सुरक्षा प्रदान करने की

व्यवस्था करें जहां कार्यक्रम होता है। (vi) जिस स्थान पर कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, उस स्थान पर एम्बुलेंस सहित पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने की व्यवस्था करें, चिकित्सा उपचार दें और ऐसे उद्देश्य के लिए एक चिकित्सा दल का गठन करें; (vii) उस स्थान पर आवश्यक पेयजल आपूर्ति के साथ-साथ स्वच्छता सुविधाओं की व्यवस्था करें जहां कार्यक्रम आयोजित किया जाना है; (viii) घटना की प्रत्येक वस्तु और व्यवस्था जैसे कि बैलों की जांच, बैलों को वश में करने वालों की जांच, बैरिकेडिंग और गैलरी की व्यवस्था, चिकित्सा सुविधाएं, जल आपूर्ति, स्वच्छता व्यवस्था और दर्शकों की सुरक्षा और घटना के संबंध में किसी भी अन्य आवश्यकता की देखभाल करने के लिए उप-कलेक्टर के पद से नीचे के अधिकारी को अधिकृत करें; (ix) पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के प्रावधानों का व्यापक प्रचार करने की व्यवस्था करें।

17. 2009 के अधिनियम की सावधानीपूर्वक जांच करने पर, यह स्पष्ट है कि घटनाओं में बैलों को वश में करना शामिल हो सकता है और जल्लीकट्टू को एक घटना के रूप में नामित किया गया है। यह सच है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर पर कुछ जिम्मेदारियां हैं कि पी. सी. ए. अधिनियम के तहत बैल के साथ कोई क्रूरता न हो। घटना की प्रकृति पर विस्तार से ध्यान देते हुए न्यायालय ने इस प्रकार कहा हैः-"जल्लीकट्टू और बैलों की दौड़ के अन्य रूप, जैसा कि विभिन्न रिपोर्टों से पता चलता है, बैलों पर काफी दर्द, तनाव और तनाव पैदा करते हैं। बैल, इस तरह की घटनाओं में, न केवल यह दिखाते हुए अपना सिर हिलाते हैं कि वे अखाड़े में नहीं जाना चाहते हैं, बल्कि वादी वसल में होने वाला दर्द इतना अधिक है कि उनके पास ऐसी स्थिति में भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं है जो उनके लिए प्रतिकूल है। उस स्थिति में बैल तनावग्रस्त, थके हुए, घायल और अपमानित होते हैं। बैलों की हताशा उनकी आवाज़ में ध्यान देने योग्य है और बैलों के चेहरे की अभिव्यक्ति को देखकर,

एथोलॉजिस्ट या एक आम आदमी आसानी से उनकी पीड़ा को महसूस कर सकता है। बैल, अन्यथा बहुत शांतिपूर्ण जानवर हैं जो मानव उपयोग और आवश्यकता के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं, लेकिन उन्हें ऐसी अग्निपरीक्षा के अधीन किया जाता है जो न केवल उन पर गंभीर पीड़ा पहुंचाती है, बल्कि उन्हें उन तरीकों से व्यवहार करने के लिए भी मजबूर करती है, अर्थात्, वे व्यवहार नहीं करते हैं, उन्हें उस घटना में मजबूर करते हैं जो पसंद नहीं है और उस प्रक्रिया में, उन्हें पूरी तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। बैल थके हुए, घायल, प्रताड़ित या अपमानित हुए बिना तथाकथित प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। बैलों को भी जानबूझकर डर, मानसिक और शारीरिक रूप से चोट पहुँचाई जाती है और मानव सुख और आनंद के लिए अनावश्यक तनाव और तनाव का सामना करना पड़ता है, वह भी एक ऐसी प्रजाति जिसने आवश्यकता के कारण मानव लाभ के लिए अपना जीवन पूरी तरह से समर्पित कर दिया है।

18. इस प्रकार, यह तर्क कि जल्लीकट्टू की घटना में उन्हें शामिल करते समय उनके साथ कोई क्रूरता नहीं की जाती है, स्वीकृति की सराहना नहीं करता है और यह 18 है। इस मामले का केंद्र यह है कि क्या ऐसा कोई अधिनियम पीसीए अधिनियम के अनुरूप है। ए. नागराजा (ऊपर) में, दो-न्यायाधीशों की पीठ ने तिरस्कार के सिद्धांतों का उल्लेख किया और उसके बाद विभिन्न प्रावधानों का विश्लेषण किया और निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः -

> "88. पी. सी. ए. अधिनियम, विशेष रूप से धारा 3, धारा 11 (1) (एम) (ii) के साथ, जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, अपराध बनाता है, यदि कोई व्यक्ति केवल अधिकार प्रदान करने की दृष्टि से किसी भी जानवर को लड़ने के लिए उकसाता है। लड़ाई किसी जानवर या इंसान के साथ हो सकती है। टी. एन. आर. जे. अधिनियम की

धारा 5 में बैल और बैल को वश में करने वालों के बीच लड़ाई की परिकल्पना की गई है, यानी बैल को वश में करने वाले को बैल से लड़ना पड़ता है और उसे वश में करना पड़ता है। अधिनियम की धारा 3 के साथ पठित पी. सी. ए. अधिनियम की धारा 11 (1) (एम) (ii) के तहत इस तरह की लड़ाई निषिद्ध है। इसलिए, टी. एन. आर. जे. अधिनियम की धारा 5 और पी. सी. ए. अधिनियम की धारा 11 (1) (एम) (ii) के बीच विसंगति है. यह मानना बेहद मुश्किल है कि न्यायालय ने अपने फैसले में तथ्यात्मक रूप से गलती की थी।

19. श्री नाफड़े का निवेदन है कि 2009 के अधिनियम की अनुचित सराहना की गई है और तिरस्कार के सिद्धांत को पूरी तरह से गलत तरीके से लागू किया गया है। यह भी सामने रखा गया है कि न्यायालय पशु कल्याण की अंतर्राष्ट्रीय अवधारणा से प्रभावित रहा है और उपनिषदों को संदर्भित करने में और गलती हुई है जिनका उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए था।

20. तिरस्कार के मुद्दे पर विचार करने से पहले, हम सोचते हैं कि हमें उस समर्पण से निपटना चाहिए जो उपनिषदों और अंतर्राष्ट्रीय धारणा के संदर्भ से संबंधित है जिसकी आलोचना की जानी चाहिए। ए. नागराजा (ऊपर) में न्यायालय ने पैराग्राफ 55 में ईशा-उपनिषद की कुछ पंक्तियों का अनुवाद किया है, जो इस प्रकार हैः -

"ब्रह्मांड अपने प्राणियों के साथ भूमि का है। कोई भी प्राणी किसी अन्य से श्रेष्ठ नहीं है। मनुष्य को प्रकृति से ऊपर नहीं होना चाहिए। किसी एक प्रजाति को अन्य प्रजातियों के अधिकारों और विशेषाधिकारों का अतिक्रमण नहीं करने दें। " हम नहीं मानते कि पशु कल्याण के संदर्भ में ईशा-उपनिषद का संकेत संदर्भ से अलग है। हम

यह सोचने के लिए इच्छुक हैं कि न्यायालय कानून और कानूनी सिद्धांतों पर विचार करते समय इस देश के सांस्कृतिक लोकाचार और प्राचीन ग्रंथों का उल्लेख कर सकता है, जहां तक कि वे संवैधानिक और वैधानिक विचार और सिद्धांत के विपरीत नहीं हैं। जहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय अवधारणा का संबंध है जो इस सोच से संबंधित है कि "जिस दुनिया को बड़ा माना जाता है वह उतनी बड़ी नहीं है" या उस मामले के लिए विभिन्न अवधारणाओं का संदर्भ जो जानवरों के प्रति करुणा और उठाए गए कदमों से संबंधित हैं। हम इसमें किसी भी कानूनी दुर्बलता को नहीं देखते हैं। यह नहीं कहा जा सकता है कि संदर्भ अनुचित है। इसके विपरीत, वे एक समग्र विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं जो हमारे संवैधानिक मूल्य के अनुरूप है। हमें कहना चाहिए कि आलोचना अनुचित है। हम ऐसा कहने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि करुणा के दर्शन में कई अभिव्यक्तियाँ हो सकती हैं।"

22. तिरस्कार के पहलू पर वापस आते हुए, हम लाभप्रद रूप से दीप सिट और (उपरोक्त) में संविधान पीठ द्वारा कही गई बातों का उल्लेख कर सकते हैं। उक्त मामले में, बहुमत ने इस प्रकार राय दी हैः - अनुच्छेद 254 (1) एक सामान्य नियम निर्धारित करता है। खंड (2) उस अनुच्छेद का एक अपवाद है और परंतुक अपवाद को योग्य बनाता है। यदि समवर्ती सूची में गिने गए मामलों में से किसी एक के संबंध में संसद द्वारा बनाई गई विधि और राज्य द्वारा बनाई गई विधि के बीच वैमनस्यता है, तो संसद द्वारा बनाई गई विधि वैमनस्यता की सीमा तक प्रबल होगी और राज्य द्वारा बनाई गई विधि, ऐसी वैमनस्यता की सीमा तक, शून्य होगी। खंड (2) के तहत, यदि किसी राज्य का विधानमंडल प्रावधानों के प्रतिकूल प्रावधान करता है। संसद द्वारा बनाए गए कानून में, यह प्रबल होगा यदि राज्य के कानून को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाए। ऐसे मामले

में भी संसद बाद में किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून में या तो संशोधन कर सकती है, बदलाव कर सकती है या उसे निरस्त कर सकती है। एम. कर्मुमिदली बनाम भारत संघ में, संविधान पीठ ने दीप चंद (उपरोक्त), ज़वेरीभाई अमीदास बनाम बॉम्बे राज्य का उल्लेख करने के बाद इस प्रकार राय दीः -

"इसलिए, ऊपर उल्लिखित अधिकारियों पर सावधानीपूर्वक विचार करने पर, निम्नलिखित प्रस्ताव सामने आते हैंः- कि तिरस्कार के प्रश्न का निर्णय करने के लिए यह दिखाया जाना चाहिए कि दोनों अधिनियमों में असंगत और अपरिवर्तनीय प्रावधान हैं, ताकि वे एक साथ खड़े न हो सकें या एक ही क्षेत्र में काम न कर सकें। 2. कि निहितार्थ द्वारा कोई निरसन नहीं हो सकता है जब तक कि दोनों कानूनों के सामने असंगति दिखाई न दे। 3. जहाँ दोनों क़ानून एक विशेष क्षेत्र पर कब्जा करते हैं, वहाँ दोनों क़ानूनों के एक दूसरे के साथ टकराव में आए बिना एक ही क्षेत्र में काम करने की गुंजाइश या संभावना है, कोई प्रतिकूल परिणाम नहीं है। 4. जहां कोई विसंगति नहीं है, लेकिन एक ही क्षेत्र पर कब्जा करने वाला एक क़ानून अलग-अलग अपराध पैदा करना चाहता है, वहां तिरस्कार का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है और दोनों क़ानून एक ही क्षेत्र में काम करते रहते हैं। चाहे यह कहा गया हो, उक्त मामले में, उड़ीसा राज्य बनाम एम. ए. का एक अंश। टुलोक्ल एंड कंपनी, को पुनः प्रस्तुत किया गया था। उक्त परिच्छेद, शिक्षाप्रद होने के कारण, यहाँ नीचे निकाला गया हैः-"असहमति तब उत्पन्न होती है जब दोनों विधानमंडलों की क्षमता के भीतर दो अधिनियम टकराते हैं और जब संविधान स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ से यह प्रावधान करता है कि एक विधानमंडल के अधिनियमन में दूसरे पर पुनर्प्राप्ति होती है तो उस हद तक कि एक दूसरे को हटा देता है। लेकिन दो अधिनियम एक दूसरे के लिए प्रतिकूल हो सकते हैं, भले ही उनमें से प्रत्येक के प्रति आज्ञाकारिता दूसरे की अवज्ञा किए बिना संभव है। हालाँकि, विरोधाभासी प्रावधानों वाले दो विधानों का परीक्षण ही तिरस्कार का एकमात्र

मानदंड नहीं है, क्योंकि यदि एक बेहतर प्रभावशीलता वाला एक सक्षम विधानमंडल अपने विधान द्वारा स्पष्ट रूप से या निहित रूप से पूरे क्षेत्र को शामिल करने का इरादा प्रकट करता है, तो अन्य विधानमंडल के अधिनियम, चाहे पहले या बाद में पारित किए गए हों, तिरस्कार के आधार पर अतिरंजित होंगे। जहाँ ऐसी स्थिति है, वहाँ असंगति दो कानूनों के प्रावधानों की विस्तृत तुलना से नहीं बल्कि केवल दो विधानों के अस्तित्व से प्रदर्शित होती है।

25. जब हम दोनों अधिनियमों का संयोजन में विश्लेषण करते हैं, तो हम पाते हैं कि जब किसी घटना के उद्देश्य से एक बैल को "वश में" किया जाता है, तो मौलिक अवधारणा पशु के कल्याण के विपरीत चलती है जो पी. सी. ए. अधिनियम की मूल नींव है। पी. सी. ए. अधिनियम और 2009 अधिनियम के बीच एक प्रत्यक्ष टकराव और स्पष्ट विसंगति है। यह अकल्पनीय है कि एक बैल जो एक घरेलू जानवर है, उसे मनोरंजन के लिए वश में किया जाना चाहिए और एक विस्तृत आधार प्रस्तुत किया जा सकता है कि यह एक टिकट वाला शो नहीं है, बल्कि फसल के त्योहार को मनाने के लिए है। कुछ लोगों को आनंद देने के लिए इस तरह का उत्सव, दोनों भाग लेने वाले और इसे देखने वाले लोग, एक ऐसा कार्य है जो जानवरों के कल्याण के खिलाफ है और निश्चित रूप से जानवरों के साथ क्रूरता के साथ व्यवहार करने के बराबर है।

26. न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि दोनों अधिनियम समवर्ती सूची डी की प्रविष्टि 17 के अंतर्गत आते हैं। समवर्ती सूची की प्रविष्टि 17 इस प्रकार हैः-"पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम।"

27. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री नाफडे ने प्रस्तुत किया है कि 2009 का अधिनियम संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टियों 14 और 15 के अंतर्गत आता है और इसलिए, वैधता का परीक्षण प्रतिकूलता पर नहीं हो सकता है।

प्रविष्टियाँ 14 और 15 निम्नानुसार हैं:-"14. कृषि शिक्षा और अनुसंधान, कीटों से सुरक्षा और पादप रोगों की रोकथाम सहित कृषि। 15. पशुओं का संरक्षण, संरक्षण और सुधार और पशु रोगों की रोकथाम; पशु चिकित्सा प्रशिक्षण और अभ्यास।

28. हम वास्तव में यह समझने में विफल हैं कि प्रविष्टि 14 का, यहां तक कि दूर से भी, जल्लीकट्टू से कोई लेना-देना कैसे हो सकता है जो एक कार्यक्रम है। केवल इसलिए कि जी घटना फसल कटाई के बाद होती है, इसे कृषि से जोड़ा नहीं जा सकता है। जहाँ तक प्रविष्टि 15 का संबंध है, इसमें पशुओं के संरक्षण, संरक्षण और सुधार और पशु रोगों की रोकथाम, पशु चिकित्सा प्रशिक्षण और अभ्यास का प्रावधान है। इस प्रविष्टि का उद्देश्य राज्य विधानमंडल को पशुओं के संरक्षण, संरक्षण और सुधार और किसी भी प्रकार के पशु रोगों को रोकने के संबंध में कानून बनाने की शक्ति प्रदान करना है।

इस प्रकार, हम बिना किसी हिचकिचाहट के मानते हैं कि जल्लीकट्टू गतिविधि पूरी तरह से सूची III की प्रविष्टि 17 के भीतर आती है और इसलिए, इसका परीक्षण तिरस्कार के आधार पर किया जाना चाहिए और यह सही तरीके से किया गया है और हमारे विश्लेषण के अनुसार, हम इसमें किसी भी प्रत्यक्ष त्रुटि को नहीं समझते हैं।

29. आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य बनाम मैकडॉवेल एंड कंपनी और अन्य मामलों में यह माना गया है कि सातवीं अनुसूची में तीन सूचियों में कई प्रविष्टियां केवल विधायी शीर्ष हैं और यह काफी संभावना है कि वे अक्सर ओवरलैप होती हैं। जहाँ कहीं भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, उस मुद्दे को पीठ और पदार्थ के नियम को लागू करके हल किया जाना चाहिए। जब भी किसी विधान के टुकड़े को राज्य विधानमंडल की विधायी क्षमता से परे कहा जाता है, तो किसी को यह पता लगाना चाहिए कि क्या वह

विधान सूची II की किसी भी प्रविष्टि के भीतर आता है। यदि ऐसा होता है, तो आगे कोई सवाल नहीं उठता। विधायी क्षमता के आधार पर हमला विफल हो जाएगा।

30. आई. टी. सी. लिमिटेड बनाम कृषि उपज बाजार समिति और अन्य मामलों में यह अभिनिर्धारित किया गया है किः - " कानून बनाने की जिस शक्ति से हम संबंधित हैं, वह अनुच्छेद 246 में निहित है। विभिन्न प्रविष्टियों में क्षेत्रों का सीमांकन किया गया है। दोनों को पढ़ने पर यह तय करना होता है कि जब इसकी वैधता पर सवाल उठाया जाता है तो क्या संबंधित विधायिका कानून बनाने में सक्षम है। किसी प्रविष्टि का दायरा और दायरा संसदीय अधिनियम के संदर्भ में निर्धारित नहीं किया जा सकता है। " हमने उपरोक्त दो प्राधिकरणों का उल्लेख किया है क्योंकि हमारी यह दृढ़ राय है कि न तो प्रविष्टि 14 और न ही प्रविष्टि 15 में से कोई भी 2009 के अधिनियम को शामिल नहीं करेगा। राज्य विधानमंडल 2009 के अधिनियम की तरह कोई कानून नहीं बना सकता था। पी. सी. ए. और 2009 का अधिनियम समवर्ती सूची की प्रविष्टि 17 के आधार पर है। हम यह कहने के लिए बाध्य हैं कि दोनों अधिनियमों के बीच विरोधाभास है और इसलिए, राज्य अधिनियम को अधिकार से बाहर घोषित किया गया है। यद्यपि श्री नाफडे ने पीठ और पदार्थ के नियम का प्रचार किया है, लेकिन इसे निरर्थकता में एक अभ्यास के रूप में माना जाना चाहिए, क्योंकि उक्त सिद्धांत लागू नहीं होता है। हमने माना है कि दोनों कानूनों के बीच टकराव है और हमने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि प्रविष्टि 17 जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम से संबंधित है और पी. सी. ए. अधिनियम पूरे क्षेत्र को शामिल करता है। इसके विपरीत, 2009 का अधिनियम बैलों को वश में करने की अनुमति देता है। इस प्रकार, दोनों सह-अस्तित्व में नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वे असंगत हैं। ए. नागराजा (ऊपर) के निर्णय में सभी पहलुओं का उल्लेख किया गया है और हमें उक्त विश्लेषण में कोई स्पष्ट त्रुटि नहीं दिखाई देती है जो पुनरीक्षण की शक्ति के प्रयोग को आमंत्रित करेगी।

31. हम अपने कर्तव्य में विफल होंगे यदि हम श्री नाफडे के समर्पण का उल्लेख नहीं करते हैं, क्योंकि उनका प्रयास भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 पर भरोसा करके 2009 के अधिनियम को बनाए रखना है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 25 जो "धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार" शीर्षक के तहत आता है, नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः-"25. विवेक और स्वतंत्र पेशे की स्वतंत्रता, धर्म का पालन और प्रचार-(।) सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य और इस भाग के अन्य प्रावधानों के अधीन, सभी व्यक्तियों को विवेक की स्वतंत्रता और स्वतंत्र रूप से धर्म का पालन करने और प्रचार करने का समान रूप से अधिकार है। (2) इस अनुच्छेद की कोई भी बात किसी भी मौजूदा कानून के संचालन को प्रभावित नहीं करेगी या राज्य को कोई कानून बनाने से नहीं रोकेगी-(ए) किसी भी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य धर्मनिरपेक्ष गतिविधि को विनियमित या प्रतिबंधित करना जो धार्मिक प्रथा से जुड़ी हो सकती है; (बी) सामाजिक कल्याण और सुधार का प्रावधान करना या हिंदुओं के सभी वर्गों और वर्गों के लिए सार्वजनिक चरित्र की हिंदू धार्मिक संस्थाओं को खोलना। स्पष्टीकरण 1- कृपाणों की चेतावनी और उन्हें ले जाना सिख धर्म के पेशे में शामिल माना जाएगा। स्पष्टीकरण 11-खंड (2) के उपखंड (ख) में हिंदुओं के संदर्भ का अर्थ सिख, जैन या बौद्ध धर्म का पालन करने वाले व्यक्तियों के संदर्भ के रूप में लगाया जाएगा और हिंदू धार्मिक संस्थानों के संदर्भ का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा।

32. अनुच्छेद 25 के तहत जो अधिकार दिया गया है, वह विवेक की स्वतंत्रता और किसी भी धर्म का पालन करने और उसे मानने के अधिकार से संबंधित है। रतिलाल पनाचंद गांधी और अन्य बनाम बॉम्बे राज्य और अन्य में संविधान पीठ ने धर्म की अवधारणा पर चर्चा करते हुए राय दी किः - " हमारे संविधान निर्माताओं ने 'धर्म' को परिभाषित करने का कोई प्रयास नहीं किया है और 'धर्म' शब्द की एक विस्तृत परिभाषा तैयार करना निश्चित रूप से संभव नहीं है जो सभी वर्गों के व्यक्तियों

पर लागू होगी। जैसा कि ऊपर उल्लिखित मद्रास मामले में संकेत दिया गया है, फील्ड्स जे. द्वारा डेविस बनाम बीसन के अमेरिकी मामले में दी गई धर्म की परिभाषा हमें पर्याप्त या सटीक नहीं लगती है। "इस प्रकार ऊपर वर्णित मामले में विद्वान न्यायाधीश ने कहा, 'धर्म' शब्द अपने निर्माता के साथ अपने संबंधों के बारे में किसी के विचारों और उनके अस्तित्व और चरित्र के प्रति सम्मान और उनकी इच्छा के प्रति आज्ञाकारिता के दायित्वों का संदर्भ देता है। यह अक्सर किसी विशेष संप्रदाय की संस्कृति या पूजा के रूप के साथ भ्रमित होता है, लेकिन बाद वाले से अलग है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि 'धर्म' आवश्यक रूप से आस्तिक नहीं है और वास्तव में भारत में बौद्ध धर्म और जैन धर्म जैसे प्रसिद्ध धर्म हैं जो ईश्वर के अस्तित्व या किसी भी बुद्धिमान प्रथम कारण में विश्वास नहीं करते हैं। निस्संदेह मान्यताओं और सिद्धांतों की एक प्रणाली में एक धर्म का अपना आधार होता है, जिसे वे लोग मानते हैं जो उस धर्म को अपने आध्यात्मिक कल्याण के लिए अनुकूल मानते हैं, लेकिन यह कहना सही नहीं होगा, जैसा कि बॉम्बे उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों में से एक ने सुझाव दिया है, कि धर्म के मामले धार्मिक विश्वास और धार्मिक विश्वास के मामलों के अलावा और कुछ नहीं हैं। धर्म केवल एक राय, सिद्धांत या विश्वास नहीं है। कृत्यों में भी इसकी बाहरी अभिव्यक्ति होती है।

33. आयुक्त, हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती, मद्रास बनाम श्री सिलिरूर मठ के श्री लक्ष्मींद्र तीर्थ स्वामीयर में यह फैसला इस प्रकार दिया गया हैः-"अनुच्छेद 25 और 26 की भाषा पर्याप्त रूप से स्पष्ट है ताकि न्यायालय विदेशी अधिकारियों की सहायता के बिना यह निर्धारित कर सके कि कौन से मामले धर्म के दायरे में आते हैं और क्या नहीं। भारत के संविधान में धर्म की स्वतंत्रता केवल धार्मिक मान्यताओं तक ही सीमित नहीं है; यह धार्मिक प्रथाओं के साथ-साथ उन प्रतिबंधों के अधीन है जो संविधान ने स्वयं निर्धारित किए हैं।

34. सरदार सैयदना ताहिर सैफुद्दीन सेल बनाम बॉम्बे राज्य मामले में अदालत ने पहले के फैसलों का उल्लेख करने के बाद कहा है कि अनुच्छेद 25 और 26 के तहत दी गई सुरक्षा सिद्धांत या विश्वास के मामले तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वे धर्म के अनुसरण में किए गए कार्यों तक भी फैली हुई हैं और इसलिए इसमें अनुष्ठानों और टिप्पणियों, समारोहों और पूजा के तरीकों की गारंटी है जो धर्म के अभिन्न अंग हैं। यह आगे देखा गया है कि किसी धार्मिक या धार्मिक प्रथा का एक अनिवार्य हिस्सा क्या है, यह अदालतों द्वारा किसी विशेष धर्म के सिद्धांत के संदर्भ में तय किया जाना चाहिए और उन प्रथाओं को शामिल करना चाहिए जिन्हें समुदाय द्वारा अपने धर्म का एक हिस्सा माना जाता है।

35. उपरोक्त अधिकारियों की गहरी सराहना पर हम यह मानने में असमर्थ हैं कि अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के साथ जल्लीकट्टू का कोई संबंध या संबंध नहीं है। श्री नाफडे द्वारा यह प्रचार किया जाता है कि प्रत्येक त्योहार की जड़ धर्म में होती है और जब जल्लीकट्टू एक ऐसा कार्यक्रम है जो फसल कटाई के बाद होता है, तो इसका धार्मिक स्वाद होता है और इस तरह के लोकाचार को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। यद्यपि उपरोक्त तर्क काफी आकर्षक है। हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि इस तरह की व्याख्या अत्यधिक विस्तारित है और अनिवार्य रूप से इसके विकर्षण में परिणाम देती है और हम ऐसा करते हैं। इस तरह की कल्पनाशील अवधारणा अनुच्छेद 25 के मौलिक पहलू के लिए पूरी तरह से अलग है और इसलिए, हम समर्पण को पीछे हटाने के लिए मजबूर हैं।

36. इससे पहले कि हम मामले को छोड़ दें, यह कहना अनिवार्य है कि भारत संघ द्वारा एक नई अधिसूचना जारी की गई है जो अन्य रिट याचिकाओं में चुनौती का

विषय है और उन पर पी. सी. ए. अधिनियम के मापदंडों के भीतर विचार किया जाएगा और इसलिए, हमने इसे स्वीकार नहीं किया है।

37. उपरोक्त विश्लेषण को देखते हुए, हम तमिलनाडु राज्य द्वारा दायर इस पुनरीक्षण याचिका में कोई योग्यता नहीं समझते हैं और तदनुसार, इसे खारिज कर दिया जाता है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

सिविल अपील संख्या 5387/2014 में पुनरीक्षण याचिका (सिविल) संख्या 3770/ 2016

1. याचिकाकर्ता की ओर से कोई पेश नहीं होता है।

2. पुनरीक्षण की मांग करने वाले तमिलनाडु राज्य द्वारा दायर आवेदन में सुनाए गए फैसले को देखते हुए, वर्तमान पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी गई है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा। पुनर्विचार याचिकाएं खारिज की गई।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक सुनील कुमार द्वारा किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा मे समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अँग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अँग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।